

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 149/2022

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थी |
|--|------|---|
| प्रकाश आजाद पुत्र श्री भरतकुमारजी जाति अग्रवाल निवासी-बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा |

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 29/09/22

01. संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बालोतरा खालसा गांव रहा है,जिसमें एक से अधिक सेटलमेंट प्रभाव में आये है,प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितिय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे में परिवर्तन किया गया। कि ग्राम बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की राजस्व रेकॉर्ड में भूमि पुराने खसरा संख्या 643 क्षेत्रफल 05 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम में से हिस्सा रकबा 11 बिस्वा श्री चुन्नीलाल पुत्र टीकमाराम जाति माली के कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि विद्यमान रही है। उक्त भूमि को प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी श्रीमति कमलादेवी पत्नि रामगोपालजी जाति अग्रवाल ने जरिये बेचान दिनांक 02.07.2014 को प्रश्नगत भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था एवं उक्त



भूमि को आवासीय उपयोग हेतु ही खरीद की गयी थी। जिसमें श्रीमति कमलादेवी ने आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु नगरपरिषद् बालोतरा से भूमि का विधि अनुसार लीज डीड दिनांक 18.09.2014 को जारी कर निष्पादित करवाया। उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरिये प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के समय राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए प्रार्थी की भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में गलत नक्शा तरमीम कर दी गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रथम सेटलमेंट के अनुसार लटढा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया तथा विवादित भूमि के संबंध में विप्रार्थी पक्ष की ओर से संशोधित जवाब पेश किया।

03. विवादित भूमि की मौका व रेकॉर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

04. प्रार्थी की ओर से डी.बी.रिट पीटीशन संख्या 544/2020 आदेश फोटोप्रति, ग्राम बालोतरा प्रथम की खसरा संख्या 643 की जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 फोटोप्रति, इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस फोटोप्रति, भूमि बेचान का एग्रीमेंट श्री चुन्नीलाल द्वारा किये गये कि फोटोप्रति, व ग्राम बालोतरा की जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 फोटोप्रति, वसीयतनामा फोटोप्रति, नगरपरिषद् बालोतरा द्वारा जारी शाश्वत लीज फोटोप्रति एवं नगरपरिषद् बालोतरा क्रमांक 10 दिनांक 14.01.2019 फोटोप्रति व नक्शा फोटो प्रति पेश की गई।

05. उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि नगर बालोतरा के सरहद मौजा बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम तहसील पंचपदश की राजस्व रेकॉर्ड में भूमि पुराने खसरा संख्या 643 क्षेत्रफल 05 बीघा 06

केसम बारानी प्रथम में से हिस्सा रकबा 11 विश्वा चुन्नीलाल पुत्र टीकमाराम जाति माली के कब्जासुदा खातेदारी की भूमि विद्यमान रही है, कि प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी श्रीमति कमलादेवी पत्नि रामगोपालजी जाति अग्रवाल ने जरिये बेचान दिनांक 02.07.2014 को प्रश्नगत भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था एवं उक्त भूमि को आवासीय उपयोग हेतु ही खरीद की गयी थी। जिसमें श्रीमति कमलादेवी ने आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु नगरपरिषद् बालोतरा से भूमि का विधि अनुसार लीज डीड दिनांक 18.09.2014 को जारी कर निष्पादित करवाया। उक्त खरीद से प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारियों एवं उनके बाद प्रार्थी का निरन्तर नियमित रूप से कब्जा चला आ रहा है प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी द्वारा विगत 40 वर्षों से ज्यादा समय से चारों ओर पत्थरों की पक्की बाउन्डरी वॉल (हदबन्दी की चार दीवारी) निर्मित की हुई है। कि प्रश्नगत भूमि प्रथम सेटलमेंट के समय के पुराना खसरा संख्या 322 का द्वितीय सेटलमेंट पर नया खसरा संख्या 643 राजस्व रेकॉर्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा अमल दरामद किया गया। द्वितीय सेटलमेंट के समय राजस्व अधिकारियों ने कभी भी प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी खातेदार टीनेन्ट को सेटलमेंट की कार्यवाही में राजस्व नक्शे लटा ट्रेस में रदोबदल हेतु सुनवाई के लिये कोई अवसर इत्यादि नहीं दिया और न उनसे कोई सम्पर्क ही किया। प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के किसी भी भूमि अथवा भू-भाग व उसके अंगा आदि पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है, न ही प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि के मालिकाना व कब्जे की भूमि कभी भी नदी के उपयोग के रूप में कभी भी नहीं रही, बल्कि मौके पर प्रश्नगत भूमि पर आदि परिसर बने हुए रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की पट्टाशुदा भूमि के द्वारा नदी की किसी भी भूमि व उसके भाग पर कभी भी कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, जो वर्तमान में नगर परिषद बालोतरा की आबादी भूमि होना मौके की प्राकृतिक वस्तुस्थिति से भी पूर्णतया स्पष्ट है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि के आस-पास सम्पूर्ण नगर पर रहवासीय परिसर बनाये जा चुके हैं और वहां आबादी कई वर्षों से बसी जा चुकी है, कि प्रार्थीगण की पट्टाशुदा भूमि का नगर बालोतरा की प्राचीन मरुगंगा लूणी नदी या उसके बहाव क्षेत्र व उसके किसी भी भू-भाग पर कोई अतिक्रमण कभी भी नहीं रहा, न था व न है। यहां यह लिखना भी समीचीन है कि नगर परिषद बालोतरा के द्वारा प्रश्नगत भूमि के आड़ोस-पाड़ोस में अवस्थित भूमियां को आबादी भूमि होना ही मानते हुए नगर परिषद



रा के द्वारा समय-समय पर विक्रय विलेख, भवन निर्माण अनुज्ञा इत्यादि भी जारी किये गये हैं एवं किये जा रहे हैं जिससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत भूमि कभी भी नदी की भूमि नहीं रही। वर्तमान में आबादी क्षेत्र के खसरा संख्या 643 की तरमीम द्वितीय सेटलमेंट के दौरान जल्दबाजी में गड़बड़ी कर गलत व अनुचित रूप से कर दी गयी, जबकि सेटलमेंट विभाग को किसी भी खसरान् की भूमि की किस्म अथवा आकृति या खातेदारी अधिकारों में कमी या अधिकता, भूमि की किस्म में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार तक प्राप्त नहीं है। यद्यपि मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति अनुसार व मूल पुराने खसरा संख्या 643 को आधार बनाकर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शा की दुरुस्ती की जाती है, तो प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र से करीब 100-150 फिट से अधिक दूरी पर है। पुराने खसरा संख्या 643 की भूमि का मुंतकिल स्थायी बिन्दु से नाप कर राजस्व नक्शा में द्वितीय सेटलमेंट के दौरान हुई गड़बड़ी से की गई त्रुटिवशं प्रविष्टि को दुरुस्त करते हुए सुधार कर रेवेन्यु रेकर्ड दुरुस्त किया जावें। अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया था, कि ऐसे में उक्त प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की स्वामित्व पट्टाशुदा कब्जासुदा की भूमि रही हैं तथा वर्तमान में आबादी क्षेत्र के नये खसरा 643 की तरमीम द्वितीय सेटलमेंट के दौरान जल्दबाजी में गड़बड़ी कर गलत व अनुचित रूप से कर दी गयी, जबकि सेटलमेंट विभाग को द्वितीय सेटलमेंट के दौरान किसी भी खसरान् की भूमि की किस्म अथवा आकृति या खातेदारी अधिकारों में कमी या अधिकता, भूमि की किस्म में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार तक प्राप्त नहीं था, जिससे अनावश्यक ही मामले में अकारण जटिलताएं उत्पन्न हो गयी। इसलिये अतिशीघ्र ही प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रथम भू-प्रबंध (प्रथम सेटलमेंट) के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। ऐसा ही अधिमत व न्यायिक दृष्टांतों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर की समय-समय पर निम्न प्रतिपादित पारित न्यायिक सिद्धान्तों व न्याय-निर्णयनों में रही है--

2022 DNJ [1] [REV.] 121 कजोड़ बनाम श्रवण, 2020 RBJ 126-2020 RRT [1] 37-2018 RRT[1] 194-2018 RRT[2] 1158-2015 RRT[2] 1214-2013 RRT[1] 391-2013 RRT [2] 1027-2010 RBJ 285-2009-10[SUPP.] RRT 337-2008 RRT [1] 151-2007 RRT[1] 27-2001 RRT[1] 244 आईदान बनाम स्टेट-2001 RBJ 170-1998 RBJ 274 इस प्रकार उपरोक्त सभी न्यायिक निर्णयों में यह

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.C.) बालोतरा

रूप से सिद्धान्त अवधारित कर प्रतिपादित किया गया कि—“Settlement Department has no competence to change the kind of land, rights of tenure-holders & entries in revenue record- He has no power to confer khatadari rights on any person- powers are limited to normal settlement operations.” अन्त में निवेदन है, कि प्रार्थी के हक हकूक पट्टाशुदा कब्जाशुदा की प्रश्नगत भूमि बालोतरा के सरहद मौजा बालोतरा पट्टवार क्षेत्र बालोतरा प्रथम तहसील पचपदरा की राजस्व रेकॉर्ड में अवस्थित आबादी क्षेत्र के नया खसरा नम्बर 643 का प्रथम सेटलमेंट के पुराने खसरान् के अनुसार ही मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति के मुताबिक ही राजस्व अभिलेख में पूर्व में द्वितीय सेटलमेंट के दौरान की गई लिपीकीय भूल व गड़बड़ी स्वरूप अशुद्ध प्रविष्टि को सुधार कर पुराने खातेदारी के खसरा संख्या के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरुस्ती करने का आदेश फरमया जावें।

6. इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस थी, कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेंट संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी, जिसका रकबा राजस्व रेकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेंट वर्ष 1967 में किया गया, तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गैर मुमकिन नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेंट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया था, कि सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन

पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के भूखण्ड परिसर गैर मुमकिन नदी में किया हुआ है, जो कि

गैर कानूनी है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि की रेकॉर्ड नक्शा दुरुस्ती करवाने के हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और कथन किया था, कि राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन



आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेंट के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थीगण किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लकड़ा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है, जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया था, पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 322 का भाग होना पाया गया था। जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात, विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं न्यायिक दृष्टांतों का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन-पत्र

अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही है, कि गत सेटलमेंट में प्रार्थी की प्रश्नगत भूमि आबादी संख्या 322 में अवस्थित थी, वर्तमान खसरा संख्या 643 है, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट के प्रार्थी की विवादित भूमि आबादी भूमि होने के उपरांत भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी की स्वामित्व पट्टाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई, जो आदिनांक तक



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बाँलोटरा

तरीके से किया गया रिकॉर्ड इन्द्राज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी की विवादित भूमि को स्वामित्व खसरा संख्या 643 की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व लटढा नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाह रहे हैं। यह तो तय है, कि गत सेन्टलमेंट के अनुसार विवादित भूमि खसरा संख्या 322 आबादी भूमि में अवस्थित थी और द्वितीय सेन्टलमेंट के दौरान प्रार्थी की विवादित भूमि आबादी में होने के उपरांत भी तत्कालीन सेन्टलमेंट अधिकारियों द्वारा गैर मुमकिन नदी में अंकन कर दी गई, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि द्वितीय सेन्टलमेंट अधिकारियों को गत सेन्टलमेंट के अनुसार ही रिकॉर्ड रिपीट करना चाहिए था। जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर 1-अपील डिक्री/टी.ए./2847/2015/दौसा व 2-अपील डिक्री/टी.ए./2848/2015/दौसा निर्णय दिनांक 04.10.2021 में प्रतिपादित किया है कि भू प्रबंध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। केवल पुरो रिकॉर्ड को दोहराने का अधिकार प्राप्त है, 2020(1)आर.आर.टी.पृष्ठ 37 में प्रतिपादित है कि भू प्रबंध विभाग इन्द्राज परिवर्तन करने हेतु सक्षम नहीं है।

सेटलमेंट-सेटलमेंट आप्रेशन-भूमि की किस्म, कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां परिवर्तित करने का सेटलमेंट विभाग को अधिकार नहीं है। जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर 1-अपील डिक्री/टी.ए./2847/2015/दौसा व 2-अपील डिक्री/टी.ए./2848/2015/दौसा निर्णय दिनांक 04.10.2021 में प्रतिपादित किया है, कि भू प्रबंध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। केवल पुराने रिकॉर्ड को दोहराने का अधिकार प्राप्त है। 2020(1) आर.आर.टी.पृष्ठ 37 में प्रतिपादित है, कि भू प्रबंध विभाग इन्द्राज परिवर्तन करने हेतु सक्षम नहीं है। 2018(1) आर.आर.टी.पृष्ठ 37 व 2015(2)आर.

आर.टी.पृष्ठ 1214 में प्रतिपादित है, कि भू प्रबंध विभाग द्वारा कारित त्रुटि को विचारण न्यायालय ने उन्नी किया-भू प्रबंध विभाग प्रविष्टियों को दोहराने हेतु बाध्य है व 2008(1) आर.आर.टी.पृष्ठ 1214 में भी प्रतिपादित किया है कि बन्दोबस्त विभाग को विद्यमान अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है, कि गत सेटलमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार ही द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों को रिकॉर्ड का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि गत सेटलमेंट के



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

र आबादी भूमि में इन्द्राज होने के उपरांत द्वितिय भू प्रबंध के समय बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृत के नदी में रेकॉर्ड इन्द्राज कर दिया गया। जिसका तत्समय द्वितिय भू प्रबंध विभाग को कोई कानूनी अधिकारी नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक था। जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्या अथवा दस्तावेज विप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया। जिससे यह जाहिर हो कि आबादी भूमि के स्थान पर गैर मुमकिन नदी का भाग इन्द्राज करने का आदेश पारित हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतों अनुसार किसी भी खातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा कमी जा सकती है और न ही जोड़ा ही जाता है। भू प्रबंध विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है,जिसके तहत मात्र पूर्व प्रविष्टि को नये नाप को दोहराना भर होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी की विवादित भूमि में हुए रेकॉर्ड में फेरबदल गत सेन्टलमेंट,के अनुसार ही दुरुस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। क्योंकि भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार का कृत्य है। साथ ही विप्रार्थी की ओर से अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है,कि पूर्व में उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था,जिसमें प्रार्थी द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया को आक्षेपित किया गया,जिस पर माननीय न्यायालय में भूप्रबन्ध की स्थिति पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक/प /14/(28)(1)भू.अ./रा.प्र.

/2018/5153 दिनांक 27.11.2020 द्वारा राजस्व विभाग एवं भू प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम गठित कर गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लेकर करवाया गया था,जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 322 का भाग होना पाया गया था,जो तत्समय प्रचलित भू प्रबंध के रेकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी। जिससे स्पष्ट साबित होता है कि विवादित भूमि नदी में न होकर

भूमि की सीमा के अन्दर है और द्वितिय सेन्टलमेंट द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन खसरे में शामिल करने में लिपिकीय त्रुटि है,जो कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का है। जहां विप्रार्थी द्वारा बिन्दु उठाया कि पूर्व प्रचलित भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त भूमि पर कब्जा/विधिक स्वामित्व होना का दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया है,उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है,क्योंकि प्रार्थी ने विवादित भूमि पर कब्जा/स्वामित्व की शाशवत लीज प्रति पेश



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.)

3। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि द्वितीय भू प्रबंध के वक्त की गई उक्त त्रुटि को माफिक प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(मिर्शा सोनी)

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 29/9/2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा